International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 6, Issue 4, April 2019
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com, editor@aarf.asia

अफगानिस्तान–पाकिस्तान के मध्य राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्ध : हामिद करज़ई शासन काल में एक ऐतिहासिक अध्ययन

फकरूदीन खान
शोधार्थी
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

प्रस्तावना

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सामरिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध स्वयं के हितो के इर्द–गिर्द घूमते हैं। अफगानिस्तान–पाकिस्तान सम्बन्ध प्रारम्भ से ही समस्याग्रस्त रहे है। जिस वजह से दोनों देशों के मध्य हमेशा एक–दूसरे के प्रति संदेह और अविश्वास रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो मुख्य पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों में ऐतिहासिक, भौगोलिक, भाषाई, जातीय और धार्मिक प्रतिबद्धता है। दोनों देश इस्लामी गणराज्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के प्रमुख सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही गैर नाटो के सहयोगी दलों के रूप में दोनों देश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक पड़ाव अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई के शासन काल में आया।[1] गत् 18 वर्षों में से तकरीबन 14 वर्ष तक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सम्बन्धों के मध्य हामिद करज़ई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दोनों देशों के बीच हामिद करज़ई शासन काल में परम्परागत रूप से चले आ रहे राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्धों ने नवीन स्वरूप धारण किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य अस्थिर सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में, करज़ई शासनकाल से पूर्व एवं करज़ई शासनकाल के दौरान, दोनों देशों के मध्य अनेक समझौते, सन्धियाँ व अनेक विचारधाराएँ विद्यमान थी, लेकिन फिर भी दोनों देशों के सम्बन्धों को साकार रूप नहीं मिल पाया। उपर्युक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुये इस शोध पत्र में दोनों देशों के बीच करज़ई शासनकाल में राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है।

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

भूमिकाः

हामिद करज़ई : एक परिचय

हामिद करज़ई, 24 दिसंबर 1957 ईस्वी में जन्म लेने वाले एक अफगान राजनेता है, जो 22 दिसंबर 2001 से 29 सितंबर 2014 तक अफगानिस्तान के सक्रिय नेता थे। 7 दिसंबर 2004 से 2014 या 10 वर्षों तक उन्होंने मूल रूप से राष्ट्रपति के रूप में शासन किया था। वह राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से थे, करज़ई के पिता, चाचा और दादा सभी अफगान राजनीति या सरकार में सक्रिय थे। करज़ई और उसके पिता अब्दुल अहद करज़ई, दुर्रानी जनजातीय संघ के पोपालजई जनजाति के प्रमुख थे।[2]

सन् 1980 के दशक में करज़ई मुजाहिदीन के लिए एक फंडराइजर के रूप में सक्रिय थे, जो सोवियत–अफगान युद्ध (1979–1989) के दौरान सोवियत सेना के सैनिकों को निष्कासित करने के लिए लड़ रहे थे। जब तालिबान 1990 के मध्य में उभरा तब करज़ई ने सोचा कि अब वे देश में हिंसा और भ्रष्टाचार बंद करने का प्रयास करेंगे। तालिबान ने करज़ई को राजदूत बनने का न्यौता भी दिया था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच जुलाई 1999 में करज़ई के पिता अब्दुल अहमद करज़ई की हत्या कर दी गई तब हामिद करज़ई ने उत्तरी गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया।[3]

1999 में हामिद करज़ई ने जीनत कुरैशी से शादी कर ली जो पेशे से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। करज़ई की तीन संताने एक बेटा और दो बेटी है। करज़ई के छः भाई और एक बहन फौजिया करज़ई है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफगान रेस्तरा के नाम रेस्टोरेंट चला रही है।[4]

11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमले के बाद, करजई ने अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने और नई सरकार के समर्थन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंटों का समर्थन किया। इसके एक वर्ष पश्चात् ही 5 सितंबर, 2002 को कंधार में हामिद करजई की हत्या का प्रयास किया गया। नई अफगान नेशनल आर्मी की वर्दी पहने एक बंदूकधारी ने कांधार के गवर्नर और एक अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस ऑफिसर को गोली मार दी, इस प्रकरण में बंदूकधारी और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में से एक को मार दिया गया।

इसके बाद 2002 के लोया जिर्गा (एक भव्य असेम्बली) के दौरान अफगानिस्तान के काबुल में आयोजित अंतरिम राष्ट्रपति चयन के रूप में उन्हें दो साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। इसके उपरान्त 3 नवंबर, 2004 को, हामिद करजई को अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र–अफगान संयुक्त निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणामों को स्वतंत्र और निष्पक्ष घोषित किया और घोषणा की कि करजई ने 55 प्रतिशत से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। 7 दिसंबर, 2004 को अफगानिस्तान के हामिद करजई ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इस तरह वे अफगानिस्तान के पहले लोकप्रिय राष्ट्रपति चुने गए।

वर्ष 2009 के दौरान अफगानिस्तान के नागरिकों ने राष्ट्रपति और प्रांतीय परिषद के चुनावों में मतदान किया, और देश के इतिहास में पहला प्रतिस्पर्धी राष्ट्रपति चुनाव में हामिद करजई को विजेता घोषित किया गया। 19 नवंबर 2009 को राष्ट्रपति करजई ने अपना दूसरा कार्यकाल संचालित किया और यह सफर सितंबर 2014 तक सफल रूप में संचालित रहा।

करजई ने अपने शासनकाल में अफगानिस्तान में गरीबी, सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक संकट, सरकारी अक्षमता, आपराधिकता और उग्रवाद के प्रति, संस्थागत और पारंपरिक अनौपचारिक शासन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पूरजोर संघर्ष किया। इसके साथ ही करजई ने अपने एक दशक से अधिक के राष्ट्रपति कार्यकाल में सदैव अपने सभी पड़ौसी देशों से वैमनस्य कम कर, शांति व सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया।

करजई के मधुर मिजाज ने उनके अंतरराष्ट्रीय समर्थकों को और अधिक प्रभावित किया। सितंबर 2010 में वाटरगेट के पूर्व जांचकर्ता और प्रसिद्ध पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने बताया कि करजई अफगानिस्तान के विकास हेतु अपने फैसले पर दृढ रहते है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्धों की गहनता बगैर दोनों देशों की विदेशनीति का स्पष्टीकरण जटिल है, यद्यपि दोनों देशों के विकास के लिए इनके मध्य मधुर सम्बन्ध आवश्यक है किन्तु समयानुसार इनमें भविष्यगत् दृष्टि अनुरूप परिवर्तन होते रहे है।

अध्ययन का उद्देश्यः

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान–पाकिस्तान के मध्य राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्ध : हामिद करज़ई शासन काल में एक ऐतिहासिक अध्ययन है।

इस विषय पर यद्यपि बिखरी हुई साम्रगी पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है परन्तु एक ही स्थान पर इकट्ठी साम्रगी का अभाव है क्योंकि इस विषय पर अभी आवश्यक और पूर्णरूपेण शोध कार्य नहीं हुआ है। इस दृष्टि से यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यद्धपि इस अध्ययन में त्रुटियाँ हो सकतीं हैं परन्तु फिर भी मैंने इस विषय पर अधिकाधिक गहन और विष्लेषणात्मक दृष्टिकोण पस्तुत करने का प्रयास किया है।

शोध प्रविधिः–

ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति के विषय में जो कुछ तथ्य प्रदान करते है, उनकी आवृत्ति उन साधनों के अन्तर्गत प्रत्यक्षतः समाहित नहीं रहती।

एक व्यक्ति जो ऐतिहासिक तथ्य के विषय में तात्कालिक घटना से सम्बन्धित व्यक्ति के मुंह से सुने–सुनाये वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, ऐसे वर्णन को द्वितीयक साधन कहते है। इनमें यद्यपि सत्य का अंश रहता है किन्तु प्रथम साक्षी से द्वितीय स्त्रोतों तक पहुँचते–पहुँचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाता है जिससे उसके दोष–युक्त होने की सम्भावना रहती है। दार्शनिक विधि के अन्तर्गत अध्ययन हेतु चुने गये मुद्दे को ही प्रारम्भिक बिन्दु माना जाता है। इसमें जिन बातों पर बल दिया जाता है उनमें मुख्यतः किसी व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र या समूह के चिन्तन में किसी दिये समय पर पाये जाने वाले विचारों की व्यवस्था या प्रभावी धारणाओं या विचारों का विश्लेषण तथा यह प्रदर्शित करना कि वे उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों, व्यवहारों तथा साहित्य में किस प्रकार प्रतिबिम्बित है या किसी महान चिन्तक या समूह विशेष के व्यक्तियों के ऐसे विचारों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना जो उनके व्यक्तिगत अभिवृत्तियों एवं चर्चाओं, जीवन एवं उपलब्धियों में प्रदर्शित होते है।

शोध अध्ययन द्वारा प्राप्त प्रतिफल

हामिद करज़ई शासनकाल में भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्ध हमेशा ही उथल–पुथल भरे रहे हैं। लेकिन हामिद करज़ई ने अपने शासनकाल में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने के भरसक प्रयास किये। काबुल में एक औपचारिक समारोह में हामिद करज़ई द्वारा 7 दिसंबर 2004 को अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के पश्चात् सोचा गया कि करज़ई 2005 में एक अधिक आक्रामक सुधारवादी मार्ग के जरिए अफगानिस्तान को सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। हालांकि, करज़ई अपेक्षा अनुरूप योग्य सिद्ध हुये, 2004 से पहले अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होने पर भी 2004 में हामिद करज़ई द्वारा प्रशासन को संभालने के बाद, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था कई वर्षों बाद वृद्धि स्तर प्राप्त करने लगी। सरकारी राजस्व हर साल बढ़ने लगा, हालांकि अफगानिस्तान अभी भी विदेशी सहायता पर निर्भर है। सन् 2001–14 के दौरान करज़ई की शासनकाल में पहली अवधि के दौरान, भ्रष्टाचार और नागरिकों में आपसी हिंसा से सार्वजनिक असंतोष बढ़ गया था। काबुल प्रांत में मई 2006 में, अमेरिकी कार्यवाही एवं करज़ई के विरोध में हुए अनेक दंगों के कारण हताहतों को उनकी सरकार ''अब स्वीकार नहीं कर सकती''।[5] सितंबर 2006 में, करज़ई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि अफगानिस्तान आतंकवाद का ''शिकार'' बन रहा है। इस अफगानिस्तानी आतंकवाद को पाकिस्तान अपने देश में पनाह दे रहा था। करज़ई ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान के जरिये देश में वापसी कर रहा है, आतंकवादियों एवं सीमावर्ती घुसपैठियों ने नागरिकों पर हमला किया है।[6] उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में इसका बीजारोपण अज्ञात है लेकिन इसके पोषण का श्रेय पाकिस्तान का रहा है। अफगानिस्तान के आन्तरिक एवं बाह्य आतंकवादी क्षेत्रों को नष्ट करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता मांगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया, आपको आतंकवाद के स्रोतों के लिए अफगानिस्तान से बाहर देखना है, और देश से दूर आतंकवादी क्षेत्रों को नष्ट करना है। इस क्षेत्र में आतंकवादियों के विस्तृत सम्पर्क को नष्ट कर दें, और सैनिकों को प्रशिक्षित कर आतंकवादियों के खिलाफ तैनात करें। इसके अलावा, उन्होंने अपने देश में अफीम–गांजे की खेती को खत्म करने का वादा किया, जो संभवतः चल रहे तालिबान विद्रोह को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। उन्होंने बार–बार आग्रह किया कि आवासीय क्षेत्रों में सैन्य संचालन करते समय नाटो सेनाएँ अफगान नागरिकों को क्षति से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतेंगी। सितंबर 2006 के प्रसारण में करज़ई ने कहा कि यदि इराक युद्ध पर बर्बाद धन वास्तव में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर खर्च किया गया होता तो उसका देश ''एक वर्ष से भी कम समय में स्वर्ग स्वरूप में होता''।[7]

अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और लोकतांत्रिककरण में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी देश रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में साथ नहीं दिया जिसके कारण पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ सम्बन्ध तनाव पूर्ण रहे, लेकिन 2004 से 2009 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका–अफगानिस्तान संबंधों में सुधार हुआ है, खासकर करज़ई प्रशासन के गठन के बाद। अन्य नाटो सदस्यों और क्षेत्रीय देशों के साथ अफगानिस्तान के विदेश संबंधों में करज़ई प्रशासन के दौरान सुधार हुआ है।[8]

2004 के बाद करज़ई अपने देश में शांति की कोशिश करने लगे और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अप्रैल 2007 में, करज़ई ने उन्होंने कुछ

आतंकवादियों के समूहों से अफगानिस्तान में शांति लाने की कोशिश करने के बारे में बात की थी। लेकिन इन समूहों ने उनकी बात को नकार दिया और सितम्बर 2007 में, अफगानिस्तान मे सुरक्षा हेतु करज़ई ने फिर से आतंकवादियों के साथ वार्ता की पेशकश की। लेकिन इस कदम से भी कोई ठोस प्रभाव नही पड़ा। अपने देश की सुरक्षा हेतु और पाकिस्तान के आतंवादियों से निपटने के लिए करज़ई ने नाटो देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किये खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, इस तथ्य के कारण कि यह प्रमुख राष्ट्र है जो युद्ध–विस्फोट अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है।[9]

अफगानिस्तान का पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सन् 2007 के बाद परिवर्तन आया और करज़ई सरकार के सम्बन्ध खासकर अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के साथ अच्छे प्रतीत हुए। वह अक्सर अपने देश और पाकिस्तान को ''अविभाज्य जुड़वां भाइयों'' के रूप में वर्णित करता है, जो दोनों राज्यों के बीच विवादित डूरन्ड रेखा सीमा का संदर्भ है। दिसंबर 2007 में, करज़ई और उनके प्रतिनिधि दो इस्लामी राज्यों के बीच व्यापार संबंधों और खुफिया साझाकरण पर परवेज मुशर्रफ के साथ सामान्य बैठक के लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान गए। करज़ई ने मुलाकात की और 27 दिसंबर 2007 की सुबह बेनजीर भुट्टो के साथ कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर लम्बी चर्चा की, वार्ता के कुछ घण्टों पश्चात ही उन्होंने चुनावी सभा को सम्बोधित किया जहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी। भुट्टो की मृत्यु के बाद, करज़ई ने उसे अपनी बहन और एक बहादुर महिला कहा, जिसने अपने देश, अफगानिस्तान और क्षेत्र के लिए – लोकतंत्र, समृद्धि और शांति के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। सितंबर 2008 में, आसिफ अली जरदारी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने के लिए विशेष यात्रा पर करज़ई को आमंत्रित किया गया था। 2008 में पीपीपी पार्टी के कब्जे के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार हुआ। दोनों राष्ट्र अब अक्सर आतंकवाद और व्यापार पर युद्ध के संबंध में एक–दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों पर हमलों की शुरुआत करने के लिए नाटो सेनाओं को भी अनुमति दी। लेकिन पाकिस्तान की पिछली सरकार द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों का दृढ़ता से विरोध किया गया। 2010 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता– अफगान–पाक ट्रांजिस्ट व्यापार समझौते (एपीटीटीए) पर हस्ताक्षर हुये। इसमें अफगान में पाक रेलवे को जोड़ने की अनुमति, अफगान ट्रकों के पाक सीमा के भीतर जाने की अनुमति तथा भारत के वाघा सीमा पर भी आने–जाने की अनुमति प्रदान करता है एवं व्यापार समस्या को हल करने के लिए 2010 में दोनों राज्यों में एक संयुक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। इस समझौते से दोनो देशों के मध्य करीब पाँच अरब डॉलर तक व्यापार पहुँचने की सम्भावना थी। आखिरकार दोनों राज्यों ने व्यापार में सुधार के इरादे से 2011 में लम्बे समय से प्रतीक्षित अफगानिस्तान–पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट कानून में हस्ताक्षर किए।[10]

राजनैतिक एवं सामरिक दृष्टि से देखा जाये तो अफगानिस्तान काफी उथल–पुथल भरा देश रहा है। 90 के दशक में सोवियत सेना की वापसी के बाद से ही, यहाँ अस्थिरता का माहौल रहा है। यह देश मुख्य रूप से अराजकता, आतंक और षड्यन्त्र का शिकार हो गया। वर्तमान में अफगानिस्तान में भले ही लोकतांत्रिक सरकार हो, किन्तु यहाँ पर चरमपंथियों के कारण सामान्य जनजीवन कठिन था। यहाँ के पर्यटन स्थल को भी क्षति पहुँची थी। तालिबान शासन के समय तो अनेक राष्ट्रों ने अफगान से राजनैतिक सम्बन्ध

तोड़ लिये थे। जिसका इस देश पर विपरीत प्रभाव देखने को मिला। ज्यादातर देशों की सरकारी और निजी कम्पनी ने इस देश में कर रहे विकासात्मक कार्यों को बन्द कर दिया। देश में अस्थिरता के चलते व्यवसायिक और आर्थिक हानि हुई। यद्यपि अफगानिस्तान के विश्व में अनेकों देशों में मैत्रीपूर्ण और व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित हैं।[11]

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध करज़ई शासन काल के दौरान तुलनात्मक दृष्टि से पूर्व अफगानिस्तानी शासकों से बेहतर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राजनीतिक सम्बन्धों पर बात कि जाये तो यह सम्बन्ध जटिल रहे हैं। अफगानिस्तान में होने वाले परिवर्तनों ने हमेशा सामान्य रूप से क्षेत्र और विशेष रूप से पाकिस्तान को प्रभावित किया है। ये दोनों देश तनाव से मुक्त द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित करने में कभी सफल नहीं हुए हैं। अफगानिस्तान में विद्रोह दोनों राज्यों के बीच तनाव का एक प्रमुख स्रोत रहा है, और पाकिस्तान विशेष रूप से अफगानिस्तान में विभिन्न शासनों के शासनकाल में सदैव एकमत न रहकर परिवर्तित रहा है।[12] जैसे–अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोह के बाद सोवियत कब्जे के दौरान मुजाहिद्दीन के पाकिस्तान में कथित सम्बन्ध दोनों राज्यों के बीच तनाव के प्रमुख स्रोत रहे हैं। इसके अलावा, इन दोनों देशों की व्यवहारिक अस्थिरता से न केवल शांति और सुरक्षा के लिए खतरा रहा है बल्कि इसके सीमावर्ती राज्यों (चीन, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान) के लिए भी, ये द्वेष व कुटिल राजनीति का आयाम बन गया है। अंत में यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्धों को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने स्वयं के शासन काल में 2001 से 2014 के मध्य नवीन आयाम प्रदान किये। इसके बावजूद अफगानिस्तान–पाकिस्तान के मध्य राजनैतिक एवं सामरिक सम्बन्धों का सार पूर्णरूप से संतोषप्रद नहीं रहा।[13]

तत्कालीन समय में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों का मुख्य आधार करज़ई का लोकतांत्रिक शासनकाल रहा। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त करजई के शासनकाल अन्तर्गत अफगानिस्तान–पाकिस्तान के राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्धों पर भारत–पाकिस्तान–अफगानिस्तान के त्रिकोणात्मक सम्बन्ध ने भी व्यापक प्रभाव ड़ाला है।

भारत–पाकिस्तान–अफगानिस्तान के त्रिकोणात्मक सम्बन्ध

हामिद करज़ई के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अफगानिस्तान के सम्बन्ध भारत के साथ ओर अधिक सुदृढ हुए है। वहीं 21वीं सदी के प्रारम्भिक दशक में भारत–पाकिस्तान के सम्बन्धों में कडवाहट बढ़ी है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव अफगान–पाक सम्बन्धों पर पड़ना लाज़मी था। तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई के एक चचेरे भाई ने 2007 में कहा था कि भारत ''अफगानिस्तान का सबसे पोषित साथी'' है। वर्ष 2006 में भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली ने बताया कि भारत ''अफगानिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दाता है और वैश्विक स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा दानदाता है, जिसकी सहायता से तीन अरब डॉलर से अधिक की सहायता मिली है। भारत ने अफगानिस्तान में 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी स्कूलों, प्रायोजकों का निर्माण किया है।''

वर्ष 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी के बाद, अफगान विदेश मंत्रालय ने भारत को ''भाई देश'' और दोनों के बीच के रिश्ते को एक ''कोई दुश्मन बाधा नहीं पहुँचा सकता'' के रूप में उद्धत किया। 2010 के गैलप पोल के अनुसार, जिसने 1,000 वयस्कों का साक्षात्कार लिया, 50 प्रतिशत अफगानियों ने भारत के नेतृत्व के काम

के प्रदर्शन को मंजूरी दी। यह एशिया के किसी अन्य देश द्वारा भारत की सर्वोच्च अनुमोदन रेटिंग थी। सर्वेक्षण के अनुसार, अफगान वयस्कों को चीनी या अमेरिकी नेतृत्व की तुलना में भारत के नेतृत्व को मंजूरी देने की अधिक संभावना दिखी।

भारत गणराज्य एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था जिसने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवियत संघ की सैन्य उपस्थिति को मान्यता दी, और अफगानिस्तान में राष्ट्रपति नजीबुल्ला की सरकार को मानवीय सहायता प्रदान की। अफगानिस्तान से सोवियत सशस्त्र बलों की वापसी के बाद, भारत ने नजीबुल्लाह की सरकार को मानवीय सहायता देना जारी रखा। इसके पतन के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर भारत ने नियंत्रण करने वाली गठबंधन सरकार का समर्थन किया, लेकिन संबंध और संपर्क एक अन्य गृह युद्ध के प्रकोप के साथ समाप्त हो गए, जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक इस्लामी आतंकवादी तालिबान को सत्ता में लाने पर आये। तालिबान शासन को केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा मान्यता दी गई थी। तालिबान द्वारा बामियान बुद्ध के स्मारकों को नष्ट करने के कारण भारत ने नाराजगी और विरोध किया।

2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के दौरान, भारत ने गठबंधन बलों के लिए खुफिया और अन्य प्रकार की सहायता की पेशकश की। तालिबान के उखाड़ फेंकने के बाद, भारत ने नव स्थापित लोकतांत्रिक सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, सहायता प्रदान की और पुनर्निर्माण के प्रयासों में भाग लिया। भारतीय सेना के सीमा सड़क संगठन ने 2009 में निमोज के सुदूर अफगान प्रांत में एक बड़ी सड़क का निर्माण किया, जो डेलाराम को जरंज से जोड़ता था। यह ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए माल की शुल्क मुक्त आवाजाही के लिए एक व्यवहार्य वैकल्पिक मार्ग साबित हुआ।

2005 में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा। दोनों राष्ट्रों ने इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ रणनीतिक और सैन्य सहयोग भी विकसित किया। भारत के हामिद करजई की यात्रा के दौरान अफगानिस्तान और भारत के बीच भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और अफगान नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी के बीच ग्रामीण विकास, शिक्षा और मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सितंबर 2011 में हुई हत्या की भारत द्वारा निंदा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि, ''दुख की बात है कि आतंक और नफरत की ताकतों ने अफगानिस्तान में शांति और शांति के लिए एक और शक्तिशाली आवाज उठाई है। हम बड़ी क्रूरता के इस कृत्य की निंदा करते हैं।'' ''और अफगानिस्तान में'' लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए शांति और प्रयासों की खोज ''में लोगों और भारत सरकार के दृढ़ समर्थन को दोहराया।'' भारत ने अफगानिस्तान के लोगों द्वारा खड़े होने का वादा किया क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय बलों की वापसी के बाद अपने शासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार थे। अक्टूबर 2011 में, अफगानिस्तान ने भारत के साथ अपने पहले रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत यात्रा के दौरान, करजई ने बताया कि ''यह रणनीतिक साझेदारी किसी भी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं है। यह रणनीतिक साझेदारी अफगानिस्तान का समर्थन

करने के लिए है।'' उन्होंने यह भी कहा कि ''पाकिस्तान हमारा जुड़वा भाई है, भारत एक महान मित्र है। हमने अपने मित्र के साथ जो समझौता किया है वह हमारे भाई को प्रभावित नहीं करेगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि ''हालांकि, इस्लामाबाद के साथ हमारा जुड़ाव दुर्भाग्य से अभी तक उस परिणाम के रूप में सामने नहीं आया है जो हम चाहते हैं।'' दोनों पक्षों ने मई 2012 में सामरिक भागीदारी समझौते को लागू करने के लिए सर्वोच्च निकाय भागीदारी परिषद का शुभारंभ किया। जब अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित होने की ओर अग्रसर हो रहा था तब भारत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का शासन था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने दीपावली अभिनंदन के लिए आये अफगानिस्तान के सांसद एवं अन्य प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में एक स्थिर, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो यह हम कामना करते हैं।

भारत और अफगानिस्तान के बीच सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बढ़ाने हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करजई 8 से 11 मार्च सन् 2003 तक चार दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आये, श्री करजई का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया, स्वागत के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री करजई ने कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी काफी मदद की है खास करके 11 सितम्बर 2001 के बाद जो अफगानिस्तान की बर्बर हालात हुई थी इस हालात को उभारने में और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में हमारी काफी मदद की है। दुसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हामिद करजई दिनाकं 9 से 13 अप्रैल सन् 2006 को पाँच दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने हेतु परस्पर अत्याधिक सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

सार्क संगठन का 14वां शिखर सम्मेलन 3–4 अप्रैल सन् 2007 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क संगठन का आठवाँ सदस्य देश बना लिया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने सार्क संगठन का सदस्य बनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया और इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने की इच्छा प्रकट की। जबकि पाकिस्तान सदैव अफगान–भारत के मधुर सम्बन्धों को अपने लिए खतरा मानने लगा था।

भारत, पाकिस्तान–अफगानिस्तान के सम्बन्धों के बीच न चाहते हुए भी जुड़ गया था। सन् 1996 से 2001 तक तत्कालीन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जो भारत–विरोधी थी उस समय से आज तक भी तालिबान के पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध है। अफगान सरकार और भारत के बीच अच्छे मधुर सम्बन्ध पाकिस्तान को खटकते है। अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते सम्बन्धों को पाकिस्तान अपने लिए खतरा मानता है। भारत द्वारा हेरात, माजार–ए–शरीफ, जलालाबाद तथा कंधार में वाणिज्य दूतावास खोले जाने के बाद से पाकिस्तान इनके माध्यम से भारतीय खुफिया एंजेसियों पर जासूसी करने और गुप्त अभियान चलाने का आरोप लगाने लगा। पाकिस्तान, अफगान खुफिया संगठन ''नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी'' पर बाकायदा नाम लेकर यह आरोप लगाता है कि वह बलूचिस्तान प्रातं में अलगाववाद फैलाने में भारत की मदद कर रहा है।

भारत–पाक–अफगानिस्तान के सीमा से नशीले पदार्थों के उत्पादन, तस्करी व्यापार और प्रयोग का नतीजा भारत के सीमा क्षेत्र में आंतकवाद बढ़ाने में हुआ। इन मादक पदार्थों की तस्करी/व्यापार से भ्रष्टाचार और अराजकता की संस्कृति हावी होती जा रही थी।

साररूप में कहा जा सकता है कि हामिद करजई के लोकतांत्रिक शासनकाल में भारत से बने घनिष्ठ सम्बन्धों ने अफगानिस्तान को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व सामरिक प्रगढ़ता तो प्रदान की है लेकिन साथ ही अफगानिस्तान –पाकिस्तान के मध्य न चाहते हुए भी सम्बन्धों में खट्टास पैदा की, यद्यपि इस बिगड़ी हालत के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सदैव भारत को अपने दुश्मन देश के रूप में परखा है। भारत का अफगानिस्तान का साथ देना, अफगानिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की नज़र में भारत की शत्रुतापूर्वक चाल समझी गयी। अतएव् यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि करजई शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों के मध्य भारत ने व्यापक प्रभाव ड़ाला है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि करज़ई के लोकतांत्रिक शासन के दौरान अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के राजनीतिक व सामरिक सम्बन्धों को प्रगढ़ता प्रदान हुयी है। राजनैतिक स्तर पर दोनों देशों के उच्च नेताओं की यात्रा के आदान–प्रदान से इन सम्बन्धों को और अधिक मजबूती मिली तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उन्होंने समान विचार व्यक्त किए। यद्यपि 1960–62 में अफगान–पाक सम्बन्धों में तनाव के कारण परस्पर व्यापार में उतार आया था, किन्तु स्थिति सामान्य होते ही आर्थिक क्षेत्रों में भी नए व्यापार समझौते सम्पन्न हुए तथा पारस्परिक सहयोग से व्यापार में वृद्धि हुई। इस अवधि की उल्लेखनीय बात थी–दोनों देशों में परस्पर व्यापार संतुलन लाना। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग एवं सौहार्द्र पनपा। इस अवधि में भारत–अफगानिस्तान–पाकिस्तान के त्रिकोणात्मक सम्बन्धों में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। विशेषकर पाकिस्तान का अमेरिका से सैनिक सहायता प्राप्त करना तथा भारत एवं अफगानिस्तान द्वारा उनका विरोध करना। यही आधार दोनों देशों की गुटनिरपेक्षता की नीति एवं शान्ति पूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों में आस्था को दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुआ।[14]

अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य राजनैतिक व सामरिक सम्बन्धों को ओर अधिक सुदृढ करने हेतु करजई ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में पाकिस्तानी सरकार से दोनों देशों में एकरूप से व्याप्त समस्याऐं जैसे– गरीबी, सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक संकट, सरकारी अक्षमता, आपराधिकता और उग्रवाद/आतंकवाद के प्रति एकमत हो प्रयास करने पर बल दिया। इसके साथ ही करजई ने अपने एक दशक से अधिक के राष्ट्रपति कार्यकाल में सदैव पाकिस्तान से शांति व सद्भाव स्थापित करने का आग्रह किया, यद्यपि वे इसमें पूर्ण सफल नहीं हो सके।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्धों में प्रारम्भ से ही दोहरी राजनीतिकरण रहा है। इन दोनों देशों में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान को वो सहायता व सहयोग नहीं मिला जो पाकिस्तान द्वारा मुहैया करवाया जा सकता था। दोनों देशों के मध्य समान कानून व इस्लामिक धर्म प्रवृत्तियां होने के बावजूद अनेक अनौपचारिक बन्धनों स्थित रहे। पाकिस्तान देश जहाँ किसी भी शर्ते पर अमेरिकी दामन को छोड़ना नहीं चाहता था, वहीं

अफगानिस्तान को न चाहते हुए भी सोवियत संघ से एकमत होना पड़ा, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव दोनों देशों के राजनैमिक व सामरिक सम्बन्धों पर पड़ा।

इसी सम्बन्ध श्रृंखला में अफगानिस्तान–पाकिस्तान सम्बन्धों पर बॉन समझौते का भी आंशिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वर्ष 2001 में 5 दिसम्बर को हुए बॉन समझौते के अनुसार अफगानिस्तान में एक अफगान अतंरिम अधिकार स्थापित करना था, जिसके तहत् उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की स्थापना करना एवं आपातकालीन ''लोया जिरगा'' (कबायली सरदारों की परम्परागत पंचायत) की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान था। लगभग् दो दशकों से हो रहे युद्ध की आग से झुलस रहा अफगानिस्तान लोकतांत्रिक देश बनने के लिए आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व हामिद करजई द्वारा किया गया। इस समझौते के समय अफगानिस्तान को सर्वाधिक सहयोग की आशा पाकिस्तान से रहीं, जों कि सकार नहीं हो पायी।

करज़ई द्वारा, अमेरिकी हमले के पश्चात् आतंकवाद के नाश के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सरकार का साथ देने में पाकिस्तान को भी सार्थक सहयोग करना था, जबकि पाकिस्तान ने इस स्थिति में तटस्थता की स्थिति को अपनाया। अफगानिस्तान को पुनःस्थिर करने और अमेरिकी हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा निभाई गई भूमिका भी दोषपूर्ण ही रही।

वर्ष 2004 में काबुल में एक औपचारिक समारोह में करज़ई द्वारा अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के पश्चात् विचार किया गया कि एक नवीन सुधारवादी मार्ग के साथ अफगानिस्तान–पाकिसतान के सम्बन्धों में बल प्रदान किया जाए, हांलाकि इस प्रयास में इस दौरान आंशिक सफलता प्राप्त हुयी एवं कुछ समय के लिए ही सही इनमें सामजंस्यपूर्ण व्यवहार की राह पकड़ी। 2004 के बाद करज़ई अपने देश में शांति की कोशिश करने लगे और पुनर्निर्माण प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अप्रैल 2007 में, करज़ई ने कुछ आतंकवादियों के समूहों से अफगानिस्तान में शांति लाने की कोशिश करने के बारे में बात की थी। जों सफल नहीं हो सकी, जिसके पीछे पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर छुपे आंतकवादियों को गुप्त सहयोग दिया जाना रहा।

अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि करज़ई ने लोकतान्त्रिक नेता के रूप में पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के अनेक प्रयास किए। उन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान में अनेक यात्राऐं की, कई समझौते किये, और दोनों देशों के बीच अनेक विवादास्पत मुद्दे पर संतोषजनक चर्चा की और उन्हें सुलझाने के अथक प्रयास किये। इसके अतिरिक्त यदि अफगानिस्तान पाकिस्तान सम्बन्धों में अगर विश्व की महान शक्तियाँ नैतिकरूप से न्यायपूर्वक एवं शांतिपूर्वक साथ दे तो यह दो मुख्य गणराज्यों की स्थिति विश्व के मानचित्र पठल पर आदर्श रूप में होती।

अफगानिस्तान के सामरिक सम्बन्धों के अन्तर्गत पड़ोसी देश पाकिस्तान की परराष्ट्रनीति में आज तक किसी भी स्तर पर स्थिरता नहीं रही है। इसकी नीति मौकापरस्त नीति रही है, उसका भविष्य चाहे जो भी हो उसे इसकी परवाह नहीं रही है। पाकिस्तान में राजनीति की आन्तरिक उथल–पुथल और अस्थिरता के कारण शान्ति व अमन बिगड़ गये है। सारा देश मजहबी जुनून की लहर की चपेट में है। जिससे शान्ति की भावना भी दूर होती जा रही है। अफगानिस्तान–पाकिस्तान सम्बन्ध जातीय, आतंकवाद, अराजकता के बीच संघर्ष अपने अस्तित्व के लिए है। दोनों देशों की स्थिति लगभग समान ही है। जैसे

ही अर्थव्यवस्था और राजनीति पटरी पर बैठने लगती है, तख्ता पलट की घटनाएँ हो जाती हैं। दोनों देशों की समस्या भी समान है और समाधान भी। अतः दोनों देशों को विकास की राह पर चलना है, तो एक दूसरे का सहयोग आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शशि.बी.सहाय, साउथ एशिया फ्रॉम फ्रीडम टु टेरोरिज्म, नई दिल्ली, ज्ञान पब्लिशिंग, हाऊस, 1998, पृ.सं. 23.
2. विष्णु प्रजापती, पॉलिटिक्स एण्ड पॉवर इन साउथ एशिया, नई दिल्ली, कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, 1998, पृ.सं. 34.
3. प्रशान्त अग्रवाल, साउथ एशिया : पीस सेक्यूरिटी एण्ड डवलपमेंट, नई दिल्ली, किलासों बुक्स, 2006, पृ.सं. 9.
4. एस.कुमार, इण्डिया एण्ड साउथ एशिया, नई दिल्ली, अनमोल पब्लिकेशन्स, 2006, पृ.सं. 23.
5. पूर्वोक्त पृ.सं. 296.
6. सतीश कनितकर, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया, नई दिल्ली, रजत पब्लिकेशन्स, 2000, पृ.सं. 46–47.
7. पूर्वोक्त पृ.सं. 267.
8. हरजीत सिंह, साउथ एशिया डिफेन्स एण्ड स्ट्रेटेजिक ईयर बुक, नई दिल्ली, पंचशील प्रंकाशन, 2007, पृ.सं. 18–20.
9. पूर्वोक्त पृ.सं. 126–131.
10. पूर्वोक्त पृ.सं. 173–178.
11. डॉ.कुलवंत कौर, पाक–अफगान रिलेशन, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, 1985, पृ.सं. 20.
12. मुसा खान जललजई, द फॉरिन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान लाहौर, अरियाना पब्लिकेशन, 2003, पृ.सं. 40.
13. फ्रेडरिक ग्रेर, पाकिस्तान : इन द फेस ऑफ अफगान कन्फ्लिक्ट 1979–85, नई दिल्ली, इण्डिया रिसर्च प्रेस, 2003, पृ.सं. 20.
14. बी.सी.उप्रेती, कन्टम्प्रेरी साउथ एशिया, नई दिल्ली, कलिंगा पब्लिशर्स, 2003, पृ.सं. 12.